

पत्रावली वास्ते बहस प्राचीन
पत्र दिनांक 14/12/2022 को
पेश हो

12/14/22 अधिवक्तागण उपस्थित। बहस
प्राचीन पत्र आ.न.वि. 11 CPC
पर खुली गई। पत्रावली वास्ते
आदेश दिनांक 21/12/2022
को पेश हो।

12/14/22 अधिवक्तागण उपस्थित। आदेश
प्राचीन पत्र आ.न.वि. 11 CPC
अलग से लिखवाया जाकर खुलाया
गया। प्राचीन का प्राचीन पत्र आ.
न.वि. 11 CPC भली-भांति साबित
होने पर स्वीकार किया जाकर
वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा
88, 92A RTA खारिज किया जाता
है। पंचादिक्री इस आशय की
जा रही है। पत्रावली निगीत होकर
गम्बर से कम होकर दाखिल पकृत है।



उपखण्ड अधिवक्ता (राजमोहर)
श्री कटरणपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पेदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 53/2013
भगवन्त सिंह बनाम रणजीत सिंह आदि
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी
(दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए आरटीए)

--आदेश--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 3) के द्वारा जगिण अधिवक्ता दिनांक : 21.12.2022

श्री रणजीत सिंह बराड के द्वारा प्रार्थना आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि
प्रार्थी ने उक्त वाद मुखालफाना कब्जा के आधार पर खातेदारी लिए जाने हेतु पेश किया है।
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिए जाने का कोई
ब्यवधान नहीं है, ना ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिए जाने का कोई विधि
है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी प्रतिपादित किया गया है कि मुखालफाना कब्जे के
आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। रणजीत सिंह ने दिनांक 21.03.2012 को उक्त भूमि
के लिए पंजीकृत बैयनामा, बेचान करके, कब्जा भूमि मुझ प्रतिवादी को सौंप दिया था। भूमि खर्गद से
लेकर आज तक प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 3) उक्त भूमि पर लगातार, शांतिपूर्वक, वेगेकटोक काविज
काश्त चला आ रहा है, इसके अलावा पटवारी हल्का की वर्ष 2013 की घटना वही से भी प्रार्थी
उक्त भूमि पर कब्जा होने बाबत ताईद होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी का उक्त भूमि
पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, इसलिए वादी को कोई वादकारण हासिल नहीं है। अतः
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र को इसी स्तर पर
खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कि नकल अप्रार्थी/वादी अधिवक्ता को दिलायी गई अप्रार्थी/वादी
अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 3) के द्वारा
दिना दस्तावेज साक्ष्य के कब्जा होना बताया है। प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 3) उक्त भूमि पर कभी
काविज नहीं रहा। आज भी वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी को वादकारण हासिल
नहीं होना, जो कानूनी बिन्दू है, जिसका साक्ष्य रिकॉर्ड पर आने के पश्चात दावा को मेरिट पर
निर्णय होगा। कानूनी बिन्दू उक्त प्रार्थना पत्र में तय नहीं किये जा सकते है। अतः जवाब प्रार्थना
पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय खर्चा खारिज फरमाया
जावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 3) के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र
मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।
वकील अप्रार्थी (वादी) के द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए
प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा प्रार्थना पत्र पर अवलोकन किया। प्रार्थी
(प्रतिवादी) के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि वादी
को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर कोई भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। माननीय
न्यायालय रवेन्स्यू बोर्ड अजमेर की फुल बेंच द्वारा भी निर्णय पारित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जा
के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा
सकते और ना ही प्रतिकूल कब्जा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मुकदमा
चलाया जा सकता है। इसलिए वादी को कोई वाद कारण हासिल नहीं है। वादी वाद
कारण हासिल नहीं होना, जो कानूनी बिन्दू है, जिसका साक्ष्य रिकॉर्ड पर आने के पश्चात दावा
को मेरिट पर निर्णय होगा। कानूनी बिन्दू उक्त प्रार्थना पत्र में तय नहीं किये जा सकते है। अतः
जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय खर्चा
खारिज फरमाया जावे।



उपखण्ड अधिकारी (राजत्व)
श्री कटरपुर

अधिवक्तागण के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए, जिनका सम्मान माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Civil Appeal No. 4096 of 2008; decided on 11th Sept. 2017 State of Uttarakhand & Anr. vs. Mandir Sri Laxman Sidh Maharaj में वर्णित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जा-प्रतिकूल-कब्जे के आधार पर वादी को सम्पत्ति के स्वामित्व के अधिकारों का प्रदान नहीं की जा सकती है।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर बेंच के न्यायिक दृष्टांत S.B. Civil Writ Petition No. 12744 of 2017 decided on 11th Sept. , 2017 Chhittar & Ors. vs. Smt. Bhanwari devi & Ors. में वर्णित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88, 15, 19 व 5(43) एवं 5(23)- कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद- प्रतिकूल कब्जा के आधार पर घोषणा हेतु वाद डिक्री नहीं किया जा सकता।

माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक सम/6198-6900 दिनांक 05.04.2019 की बिन्दु संख्या 19 के अनुसार जिन मामलों में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार मांगे जाते हैं उनका निस्तारण मण्डल की पूर्ण पीठों द्वारा निम्न मामलों में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार किया जाए-

1. 2011 RRD 508 जगदीश एवं अन्य बनाम सीताराम व अन्य
2. 2018 RRD 715 सरजू राव बनाम अमृत लाल

2018 RRD 715 सरजू राव बनाम अमृत लाल के निर्णय अनुसार "After giving an exhaustive consideration to the matter in hand, we are also constrained to note that in the Rajasthan Tenancy Act, 1955, there is no provision in whom the khatedari rights would vest in case the land has been acquired by a person through adverse possessor." अर्थात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई भी प्रावधान नहीं है।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि वादी का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है। इसलिए वादी को कोई वाद कारण हासिल नहीं है। वादी को कोई वादकारण हासिल है या नहीं, इसके लिए वाद पत्र का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा वाद पत्र में अंकित किया है कि वादी को उक्त भूमि का 21 वर्षों के मुखालफाना कब्जा के आधार पर खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अनुतोष चाहा गया है। इसलिए वादी का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित कहा जा सकता। प्रार्थी के द्वारा बहस में उल्लेखित माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत के सम्मानपूर्वक अवलोकन से न्यायिक दृष्टांत के निर्णय इस प्रकरण पर चर्चा होते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी (प्रतिवादी) के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादपत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। प्रार्थना पत्र सामिल पत्रावली रहे।

आदेश आज दिनांक 21.12.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
महाराजपुरी (अजमेर)
श्री कृष्णपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
भगवन्त सिंह बनाम रणजीत सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88, 92ए आरटीए मुकदमा नं. 53/2013

निर्णय दिनांक :- 21.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.) व हाजरी वादी अधिवक्ता सतीश कुमार अरोडा व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री बराड पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थी (सुभाष चन्द्र) का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी भली-भांति साबित होने पर स्वीकार जाकर वादी वाद अंतर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी धारा पर खारिज किया जाता है।
आज दिनांक 21.12.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर (राजस्व)

श्री कल्याणपुर

	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
मुददई	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
स्टाम्प इयूटी	04	00	योग	04	00
योग					



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर (राजस्व)

श्री कल्याणपुर